भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

पुरी ने भारत को 'डेड इकोनॉमी' कहे जाने पर दिया करारा जवाब

हरित-आईटी क्रांति और कोविड डिजिटल उछाल को किया याद

नई दिल्ली, 1 सितंबर. केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत विरोधी डेड इकोनॉमी वाले बयान का खंडन करते हुए देश की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डाला है. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है.

एक लेख में पुरी ने लिखा कि किसी भी महान सभ्यता की परीक्षा उसके कठिन क्षणों में होती है. उन्होंने कहा कि अतीत में जब भी संदेह हुआ, भारत ने हरित क्रांति, आईटी क्रांति और कोविड-19 महामारी से मिले डिजिटल उछाल के साथ जवाब दिया है.

मंत्री ने कहा कि भारत को %डेड इकोनॉमी% कहने वालों के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेज विकास, मजबूत बफर और व्यापक अवसरों के साथ एक मजबूती की कहानी उभर रही है. उन्होंने कहा कि यह विकसित भारत का क्षण है, जो ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा परिवर्तन प्राप्त करने की दिशा में भारत की अथक यात्रा को दर्शाता है.

पुरी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जो तेजी से बढ़ने के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से भी आगे निकल गई है. उन्होंने कहा कि वर्तमान गति के अनुसार, भारत इस दशक के अंत तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है.

> केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की गति वैश्विक स्तर पर मायने रखती है. अनुमान बताते हैं कि भारत पहले से ही वैश्विक आर्थिक विकास में 15 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे रहा है और प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा है कि यह हिस्सेदारी 20 प्रतिशत तक बढ़े.

वीई कमर्शियल व्हीकल्स की अगस्त बिक्री में 9.5% की वृद्धि

नई दिल्ली, 1 सितंबर. आयशर मोटर्स लिमिटेड की इकाई, वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (वीईसीवी) ने अगस्त में अपनी कुल बिक्री में 9.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, जो 7,167 इकाइयों तक पहुँच गई है. यह आंकड़ा अगस्त 2024 में बेची गई 6,543 इकाइयों की तुलना में उल्लेखनीय है. कंपनी द्वारा शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, अगस्त 2025 की कुल बिक्री में आयशर ब्रांड की 6,924 इकाइयां और वोल्वो ब्रांड की 243 इकाइयां शामिल हैं. घरेलू वाणिज्यिक वाहन बाजार में भी आयशर ब्रांड के ट्रक और बसों की बिक्री में पांच प्रतिशत का उछाल देखा गया. पिछले महीने 6,331 इकाइयां बिकीं, जबकि अगस्त 2024 में यह संख्या 6,023 थी.

तकनीक और सामाजिक बदलाव का संगम

नया मोबाइल ऐप प्रतिभागियों के अनुभव बेहतर बनाने कई सुविधाएं देगा

नई दिल्ली, 1 सितंबर.केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 केवल 5जी, 6जी, एआई, आईओटी और मशीन-टू-मशीन संचार जैसी तकनीकों पर चर्चा का मंच नहीं होगा, बल्कि यह समझने का भी एक मंच होगा कि ये तकनीकें किसानों, छात्रों और पूरे समाज के जीवन को कैसे बदल सकती हैं.

नया मोबाइल ऐप प्रतिभागियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई सुविधाएँ प्रदान करेगा, जैसे कि सेशन की लाइव स्ट्रीमिंग, एआई-आधारित व्यक्तिगत सुझाव, और सहज शेड्यूलिंग. यह ऐप प्रतिनिधियों, प्रदर्शकों और स्टार्टअप्स के बीच नेटवर्किंग को भी बढ़ावा देगा, जिससे स्टार्टअप्स को सलाहकारों और निवेशकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा.

ऐप का एक अन्य प्रमुख आकर्षण इसका एआई-पावर्ड स्निपेट टूल है, जो महत्वपूर्ण सेशन के छोटे वीडियो क्लिप अपने आप बनाएगा. इसके अलावा, एक को-पायलट चैटबॉट सेशन, स्पीकर, लॉजिस्टिक्स और आस-पास की सुविधाओं के बारे में तुरंत जवाब देने के लिए एक डिजिटल सहायक के रूप में काम करेगा. प्रतिभागियों को जोड़े रखने इन-ऐप फोटो बूथ, एआई-पावर्ड फेस रिकग्निशन गैलरी जैसे फीचर्स भी इसमें शामिल किए गए हैं.

> 8 से 11 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले आईएमसी 2025 के लिए एआई-पावर्ड मोबाइल एप्लिकेशन के लॉन्च के अवसर पर, सिंधिया ने कहा कि इस वर्ष के आयोजन का उद्देश्य नवाचार और परिवर्तन है, जो प्रधानमंत्री के 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों को दर्शाता है. उन्होंने इस आयोजन को संभावनाओं का मंच बताया, जहाँ ये संभावनाएँ जुड़ाव, सहयोग और परिणामों में बदलेंगी.

कपड़ा निर्यातकों को राहत

ब्रिटेन समझौता बनेगा गेम चेंजर

नयी दिल्ली, 1 सितंबर, केयरएज रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों से भारतीय कपड़ा निर्यात को हो रहे नुकसान की भरपाई, ब्रिटेन के साथ हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से हो सकती है.

अमेरिकी शुल्कों के कारण 2026 में भारत का कपड़ा निर्यात 9-10 प्रतिशत तक घट सकता है, जिससे निर्यातकों के मार्जिन में भी 300-500 बीपीएस की गिरावट आ सकती है.रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत-यूके एफटीए भारत के रेडीमेड गारमेंट्स (आरएमजी) और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों के लिए एक %गेम चेंजर% है. इसके अलावा, यूरोपीय संघ के साथ

जारी एफटीए वार्ता भी नए रास्ते खोल सकती है.

केयरएज रेटिंग्स के विश्लेषकों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा कपास पर आयात शुल्क हटाने जैसे समर्थन से निर्यातकों को मदद मिलेगी. वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी शुल्कों का भारत के निर्यात पर अल्पकालिक असर होगा, लेकिन समग्र अर्थव्यवस्था पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव सीमित रहेगा.

मानव संसाधन प्रबंधन में पावरग्रिड को स्कोप एमीनेंस अवार्ड

सीएमडी रविंद्र कुमार त्यागी और निदेशक डॉ. यतींद्र द्विवेदी ने पुरस्कार ग्रहण किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में किया सम्मानित

समारोह में केंद्रीय वित राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी रहे मौजूद

नई दिल्ली, 1 सितंबर.विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसयू, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को मानव संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 'स्कोप एमीनेंस अवार्ड' से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया.

पावरग्रिड की ओर से यह पुरस्कार कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रविंद्र कुमार त्यागी ने निदेशक (कार्मिक) डॉ. यतींद्र द्विवेदी के साथ ग्रहण किया. इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के डीपीई सचिव के. मूसा चलाई सहित अन्य सीपीएसयू, स्कोप और पावरग्रिड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

यह सम्मान पावरग्रिड की प्रगतिशील मानव संसाधन प्रथाओं को दर्शाता है, जो कर्मचारी-केंद्रित नीतियों, सतत कौशल विकास और नेतृत्व के विकास पर केंद्रित हैं. कंपनी ने नवाचार, समावेशिता और कर्मचारियों के समग्र कल्याण की संस्कृति को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

> पावरग्रिड ने 286 सब-स्टेशन और 1,80,849 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) से अधिक ट्रांसमिशन लाइनों के साथ-साथ 5,74,331 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता को चालू किया है. नवीनतम तकनीकी उपकरणों, स्वचालन और डिजिटल समाधानों के उपयोग के साथ, पावरग्रिड ने 99.85% से अधिक की औसत ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता बनाए रखी है.

भारत की लगेज इंडस्ट्री 2026 तक 5-7% की दर से बढ़ेगी : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 1 सितंबर. भारत की 18,000 करोड़ रुपए की लगेज इंडस्ट्री वित्त वर्ष 2026 में 5-7 प्रतिशत की मजबूत दर से बढ़ने की उम्मीद है. यह वृद्धि पिछले तीन वर्षों की 3 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में काफी अधिक है.

क्रिसिल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है.रिपोर्ट के अनुसार, इस मजबूत वृद्धि का मुख्य कारण छुट्टियों और कॉर्पोरेट यात्रा में आई तेजी है, साथ ही हार्ड लगेज की बढ़ती मांग भी इसमें योगदान दे रही है.

रेटिंग एजेंसी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026 तक नए जमाने के मैन्युफैक्चरर्स अपनी बाजार हिस्सेदारी को मौजूदा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग 25 प्रतिशत कर लेंगे. इसके विपरीत, पुराने और स्थापित मैन्युफैक्चरर्स की वृद्धि दर एकल अंक में ही रहने की संभावना है. संगठित सेगमेंट की कंपनियाँ इस वृद्धि में सबसे अधिक योगदान देंगी, जिनके पास कुल बाजार का 45 प्रतिशत हिस्सा है.

विश्लेषकों ने कहा कि नए जमाने के निर्माताओं की सफलता का राज उनके आधुनिक और स्टाइलिश डिजाइन, ई-कॉमर्स विस्तार, कम लागत वाले निजी लेबल-आधारित उत्पादन और नियंत्रित ओवरहेड्स में निहित है. इसके अलावा, कच्चे माल की कीमतों में कमी के कारण इस वित्त वर्ष में परिचालन मार्जिन 150-200 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर 9.5-10.0 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है.

> रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरी उपभोक्ता अब केवल टिकाऊपन पर ही नहीं, बल्कि सौंदर्य, डिजाइन और उपयोगिता पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. वहीं, ग्रामीण उपभोक्ता भी धीरे-धीरे पारंपरिक सामानों से अधिक आधुनिक और आकर्षक सामानों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं.

जल्द लागू होंगे ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम

नई दिल्ली, 1 सितंबर. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) के सचिव एस. कृष्णन ने सोमवार को कहा कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए जल्द ही नए नियम लागू होंगे. उन्होंने कहा कि अधिसूचना में अधिक समय नहीं लगेगा.

एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से बात करते हुए कृष्णन ने कहा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, मैं अभी कोई सटीक तारीख नहीं बता सकता, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो काफी जल्दी प्रभावी होगा, और हम इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं.

असली पैसों वाले खेलों पर लगेगा प्रतिबंध

लत और वित्तीय जोखिमों पर लगेगी रोक

यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत 2 से 4 सितंबर तक यशोभूमि, दिल्ली में %सेमीकॉन इंडिया 2025% की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है. इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसमें वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं के साथ एक सीईओ राउंडटेबल भी शामिल होगा.

पिछले महीने, संसद ने ऑनलाइन गेमिंग विनियमन और संवर्धन विधेयक, 2025% पारित किया था, जिसमें लत और वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए असली पैसों वाले ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

चांदी वायदा 1.24 लाख पार, 14 साल का रिकॉर्ड

नयी दिल्ली,1 सितंबर. वायदा बाजार में प्रतिभागियों के अपना दांव बढ़ाने से चांदी की वायदा कीमत सोमवार को 2597 रुपये की तेजी के साथ 1.24 लाख रुपये के स्तर को पार कर गई.मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में दिसंबर आपूर्ति वाले चांदी के अनुबंधों की कीमत 2,597 रुपये या 2.13 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 1,24,470 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. विश्लेषकों ने बताया कि प्रतिभागियों के ताजा सौदे करने से चांदी की कीमतों में तेजी आई.

उर्वरक उद्योग पर नए नियम भारी

छोटे एवं मझोले उद्यमों के बंद होने का खतरा

नई दिल्ली, 1 सितंबर. भारत का विशेष उर्वरक उद्योग नए नियमों से जूझ रहा है जिसके तहत %बायोस्टिमुलेंट% जैसे उत्पादों को पहली बार सरकारी विनियमन के दायरे में लाया गया है. उद्योग निकाय ने आगाह किया है कि इन अनुपालन संबंधी चुनौतियों के कारण कई छोटे विनिर्माताओं को अपना काम बंद करना पड़ सकता है.

उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) में फरवरी 2025 के संशोधन ने %बायोस्टिमुलेंट% क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर

दी हैं, जो करीब एक दशक तक बिना किसी विनियमन के संचालित होता रहा है. बायोस्टिमुलेंट ऐसे पदार्थ या सूक्ष्मजीव होते हैं जो सीधे तौर पर पोषण दिए बिना पौधों की वृद्धि और विकास को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

समाचार विशेष

मोदी-शाह का खेल बिगाड़ेंगे ठाकरे-पवार!

उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी से की मुलाकात

मंबई. देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद रिक्त हुए उप राष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाला चुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है. क्योंकि विपक्षी दलों के 'इंडिया' गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं.

इसी मिशन के तहत शुक्रवार को मुंबई पहुंचे रेड्डी ने 'इंडिया' गठबंधन में शामिल प्रमुख सहयोगी दल राकां शरदचंद्र पवार के प्रमुख नेता शरद पवार तथा शिवसेना यूबीटी के पक्ष प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की. इस मुलाकात के उपरांत महाराष्ट्र के दोनों प्रमुख नेताओं ने सुदर्शन रेड्डी को पूर्ण समर्थन का विश्वास दिलाया. इस मौके पर उद्धव ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बताया.

एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को बनाया उम्मीदवार- बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है. इस चुनाव में एनडीए ने राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर दक्षिण भारत में अपनी पैठ मजबूत बनाने तथा इंडिया गठबंधन में दरार डालने का दांव चला था. लेकिन वहीं विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी का गेम बिगाड़ दिया है.

स्टालिन और रेवंत से बिहार में क्या फायदा?

पार्टी का मकसद गठबंधन के अंदर अपनी ताकत दिखाना है

पटना. बिहार में चल रही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन शामिल हुए. उससे एक दिन पहले मंगलवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शामिल हुए थे. उससे पहले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अपने विशेष विमान से बिहार पहुंचे थे.

अब सवाल है कि दक्षिण भारत के बड़े बड़े नेताओं को बिहार में उतार कर कांग्रेस क्या फायदा लेना चाहती है? क्या इन नेताओं से बिहार में कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे? इस बात की कोई संभावना नहीं है कि इन नेताओं से वोट बढ़ेंगे.

कांग्रेस और राजद के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान

बिहार में वोट के नुकसान का जोखिम उठा कर कांग्रेस पार्टी अगर इन नेताओं को वोटर अधिकार यात्रा में ला रही है तो उसका मकसद गठबंधन के अंदर अपनी ताकत दिखाना है. ध्यान रहे बिहार में गठबंधन के अंदर अभी सब कुछ तय नहीं है. कांग्रेस और राजद के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है और अभी तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया है. इससे राजद में नाराजगी है. दोनों पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीट के लिए दबाव बना रही हैं.

खुला राज निषाद क्यों नाराज?

संजय के पैरों तले जमीन खिसका रही बीजेपी, यूपी में बढ़ा सियासी बवाल!

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद अपने तेवरों के कारण चर्चा में हैं. कुछ दिन पहले जब दिल्ली में निषाद पार्टी का स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ था, तो उसमें उत्तर प्रदेश में एनडीए में शामिल सभी दल मौजूद थे, लेकिन भाजपा को आमंत्रित नहीं किया गया था.

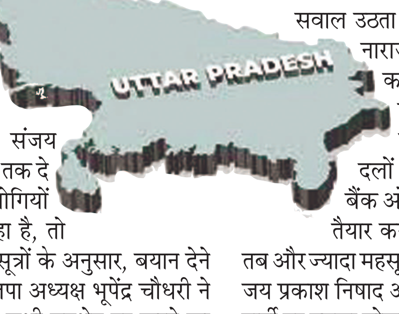

यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने भाजपा को चुनौती तक दे डाली थी कि अगर उसे सहयोगियों से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो गठबंधन तोड़ देना चाहिए. सूत्रों के अनुसार, बयान देने के बाद उसी रात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने निषाद को फोन करके उन्हें सभी मतभेद दूर करने का आश्वासन दिया था. संजय निषाद ने तो यहां तक चेतावनी दी थी कि अगर आरक्षण की मांग पूरी नहीं हुई, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव किया जाएगा. योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी घेराव की बात का समर्थन किया था.

सवाल उठता है कि संजय निषाद किस बात से नाराज हैं? निषाद पार्टी के नेताओं का कहना है कि संजय निषाद की नाराजगी की वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी छोटे दलों को लगता है कि पार्टी उनके वोट बैंक ओबीसी समुदायों के बीच अपने नेता तैयार कर रही है. निषाद पार्टी को यह बात तब और ज्यादा महसूस हुई जब भाजपा के निषाद नेताओं जय प्रकाश निषाद और साध्वी निरंजन ज्योति ने निषाद पार्टी पर हमला बोला था.

विशेष नहीं बचा कोई 'विपक्ष का नेता', राज्य में सियासी हलचल तेज

महाराष्ट्र में महायुति का एकछत्र राज!

मुंबई. महाराष्ट्र अब विपक्ष के नेता के बगैर ही चलेगा. महाराष्ट्र विधानसभा में पहले ही विपक्ष नेता विहीन है. उस पर विधान परिषद में विपक्ष के नेता रहे शिवसेना (यूबीटी) पार्टी के विधायक अंबादास दानवे का कार्यकाल भी 28 अगस्त 2025 को समाप्त हो गया है. पिछले मानसून सत्र में सरकार ने उनका विदाई समारोह भी संपन्न करा दिया था. ऐसे में महाराष्ट्र का विपक्ष अब पूरी तरह से विपक्ष के नेता विहीन हो गया है.

विधानसभा चुनाव 2024 में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में शामिल किसी भी घटक दल को विपक्ष का नेता पद पाने लायक सफलता नहीं मिली थी. विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने 20 सीटें जीतीं हैं. तो वहीं कांग्रेस ने 16 और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) ने 10 सीटें जीतीं. समाजवादी पार्टी-2 और सीपीआई (एम) की-1 सीट को मिलाने से विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी के 49 विधायक होते हैं.

288 विधायकों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता के लिए 10 फीसदी सीट के फार्मूले के हिसाब से किसी भी विपक्षी दल के पास पर्याप्त संख्याबल यानी अपने अकले 29 विधायक नहीं हैं.

शिवसेना (यूबीटी) ने ठोका है दावा

सत्ता पक्ष का दावा है कि पर्याप्त संख्या बल नहीं होने पर किसी पार्टी को विपक्ष के नेता का पद दिया जाए या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के विवेक पर निर्भर होगा. लेकिन विधानसभा सचिवालय ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में कहा था कि विपक्ष के नेता पद के लिए कोई लिखित नियम उपलब्ध नहीं है. इसलिए विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायकों वाला विपक्षी दल होने की वजह से यूबीटी ने विपक्ष के नेता पद पर दावा ठोक रखा है.